

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 मार्च, 2012

विषय:-मै0 रीजेन्सी गंगानी ऐनर्जी प्रा0लि0, रिवर ब्यू लेन शमशेरपुर पौंटा साहिब,हिमाचल प्रदेश हाल सरुखेत तहसील बडकोट को ग्राम किसाला एवं थान के अन्तर्गत 8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु 4.503 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-1866/सात-भूलेख/2009 दिनांक-17 फरवरी 2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-28/भूकय/18(1)/2005 दिनांक 03-05-2005 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मै0 रीजेन्सी गंगानी ऐनर्जी प्रा0लि0, रिवर ब्यू लेन शमशेरपुर पौंटा साहिब,हिमाचल प्रदेश हाल सरुखेत तहसील बडकोट को ग्राम किसाला एवं थान के अन्तर्गत 8 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु 4.503 है0 भूमि कय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, उर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्या के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (लघु जल विद्युत परियोजना) के लिये करेगा,



जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- संस्था द्वारा उर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के साथ पूर्व में किये गये परियोजना के कियान्वयन अनुबन्ध के अनुसार समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की जायेगी। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य हेतु किये जाने पर उक्त भूमि स्वतः ही राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

8- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित ईकाई का होगा।

10- ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में, उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

13- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(कुँवर राजकुमार)  
सचिव।

पृ०प०सं०- 369 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- मै० रीजेन्सी गंगानी ऐनर्जी प्रा०लि०, रिवर ब्यू लेन शमशेरपुर पौंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश हाल सरुखेत तहसील बडकोट(उत्तरकाशी)
- 6- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव।